



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24092020-221951
CG-MH-E-24092020-221951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942

No. 374]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2020

सं.टीएएमपी/79/2015-केपीटी —महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, दीनदयाल पत्तन न्यास की नमक-भूमि की दरों के मौजूदा दरमानों की वैधता में संलग्न आदेशानुसार विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं.टीएएमपी/79/2015-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i). श्री टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितंबर, 2020 के 7 वें दिन पारित)

यह मामला, दीनदयाल पत्तन न्यास(डीपीटी) की नमक-भूमि की दरों के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1. कांडला में नमक भूमि के मौजूदा दरमानों (एसओआर) को पिछली बार प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएमपी/79/2015-केपीटी दिनांक 02 मई 2016 द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में 26 मई 2016 को अधिसूचित किया गया था। आदेश में दरमानों की वैधता 04 जुलाई 2020 तक निर्धारित की गई थी।

2.2. डीपीटी ने 23 जून 2020 के अपने पत्र में उल्लेख किया है कि डीपीटी ने भूमि प्रबंधन पर नीति दिशानिर्देशों के प्रावधान 13 (v) के अनुसार भूमि के बाजार-मूल्य का आकलन करने के लिए भूमि मूल्यांकन-कर्ता की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिसंबर 2019 के दौरान कार्रवाई शुरू की और बंदरगाह द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इसलिए, डीपीटी ने कहा है कि 05 जुलाई 2020 से लागू संशोधित दरों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। इसलिए, डीपीटी ने मौजूदा एसओआर की वैधता 4 जुलाई 2020 से आगे अर्थात् नमक भूमि के मौजूदा दरमानों की समाप्ति की तारीख से 4 जनवरी 2021 तक 2% वृद्धि के साथ बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3.1. उपरोक्त के मद्देनजर और कांडला में मौजूदा नमक भूमि की अवधि की वैधता 05 जुलाई 2020 को समाप्त हो गई है और डीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, यह प्राधिकरण डीपीटी की कांडला में नमक भूमि के मौजूदा दरमानों की वैधता का 05 जुलाई 2020 से 04 जनवरी 2021 तक या संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है। डीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह 15 अक्टूबर 2020 से पहले नमक भूमि के लिए पट्टा-किराया में संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दायर करे।

3.2. इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी 2014 की संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश, जिनके आधार पर डीपीटी की नमक भूमि के लिए दर संरचना को मई 2016 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया, में यह निर्धारित है कि इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लीज किराया को 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा उनमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है। इस प्राधिकरण द्वारा मई 2016 में पारित आदेश में भी इस संबंध में एक विशिष्ट शर्त निर्धारित की गई है। चूंकि मौजूदा दर संरचना में किराया में पहले से ही उस समय तक और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जब तक कि दरों में इस प्राधिकरण द्वारा संशोधन नहीं कर दिया जाता है और डीपीटी के अनुरोध के अनुसार, 2% वार्षिक दर से वृद्धि निर्धारित है, डीपीटी के कांडला में नमक भूमि के लिए दर संरचना की विस्तारित वैधता अवधि के दौरान 2% की वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी।

3.3. हालांकि, इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 2% की इस वार्षिक वृद्धि के साथ मौजूदा पट्टा किराया में वैधता में यह विस्तार, वर्तमान परिदृश्य में एक वैक्यूम से बचने के लिए केवल एक अनंतिम व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर किए जाने के प्रस्ताव के आधार पर कांडला में नमक-भूमि के लिए निर्धारित किए जाने वाले पट्टा किराया को पूर्व-व्यापी प्रभाव दिया जाए, जैसा कि डीपीटी द्वारा अनुरोध किया गया है।

4. परिणामतः, और ऊपर दिए गए कारणों से यह प्राधिकरण दीनदयाल पत्तन न्यास की कांडला में नमक भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता अवधि का डीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले टैरिफ प्रस्ताव के आधार पर 05 जुलाई 2020 से 04 जनवरी 2021 तक या संशोधित पट्टा किराया की अधिसूचना की प्रभावी तिथि, जो भी पहले हो, तक विस्तार करता है। डीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह 15 अक्टूबर 2020 से पहले नमक भूमि के लिए पट्टा किराया में संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दायर करे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-3/4/असा./232/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 8th September, 2020

No. TAMP/79/2015-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of Salt Land of Deendayal Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**Case No. TAMP/79/2015-KPT****The Deendayal Port Trust**

- - -

Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 7th day of September 2020)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of Salt Land of Deendayal Port Trust (DPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of Salt land at Kandla was last approved by the Authority vide Order No.TAMP/79/2015-KPT dated 02 May 2016 which was notified in the Gazette of India on 26 May 2016. The Order prescribed the validity of the SOR till 04 July 2020.

2.2. The DPT has, vide its letter dated 23 June 2020, now submitted that the DPT has initiated action inviting offers for appointment of land valuer for assessing the market value of land as per provision 13(v) of Policy Guidelines on Land Management, 2015 during the month of December 2019 and same is under examination by the port. Therefore, the DPT has stated that the finalization of revised rates applicable with effect from 05 July 2020 will take some time. Hence, DPT has requested to extend the validity of the existing SOR beyond 4 July 2020 i.e. from the date of expiry of existing SOR of Salt land till 4 January 2021 with 2% escalation.

3.1. In view of the above and since the validity of the exiting SOR of Salt lands at Kandla has expired on 05 July 2020 and based on the request made by the DPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of the Salt Lands at Kandla of the DPT from 05 July 2020 till 04 January 2021 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier. The DPT is advised to file its proposal for revision of lease rent for salt land before 15 October 2020.

3.2. Further, the revised Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government based on which the rate structure for Salt lands of DPT has been approved by this Authority in May 2016 stipulate that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by the Authority. The Order approved by this Authority in May 2016 also prescribes a specific condition in this regard. Since the existing Rate structure already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by this Authority and in line with the guidelines issued by the Government and as requested by the DPT, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Salt lands at Kandla of DPT.

3.3. However, in this regard, it is relevant to mention here that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current

scenario. The lease rentals to be fixed for the Salt lands at Kandla based on the proposal to be filed by the DPT in this regard may have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

4. In the result, and for the reasons given above, this Authority extends the validity of the existing rate structure of Salt lands at Kandla of Deendayal Port Trust from 05 July 2020 till 04 January 2021 or the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier. The DPT is advised to file its proposal for revision of lease rent for salt land before 15 October 2020.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-3/4/Exty./232/2020-21]